कोचिंग इंडस्ट्री

शिक्षा अब उद्योग और छात्र उसके ग्राहक...

भारत की शिक्षा व्यवस्था २०२५ में कोचिंग इंडस्ट्री के कब्ज़े में है। कोटा से दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई–हर बड़ा शहर एक हाई-प्रेशर हब बन चुका है जहाँ छात्रों पर १२-१६ घंटे पढ़ाई, लगातार टेस्ट, और असफलता के डर का दबाव है। महंगी फीस, भीड़भाड़ वाले बैच, कमजोर मानसिक-स्वास्थ्य सपोर्ट और अवास्तविक सामाजिक अपेक्षाएँ मिलकर छात्रों को थका रही हैं। सवाल सिर्फ 'कोचिंग सेंटर बनाम छात्र' का नहीं है–पूरी व्यवस्था छात्रों को नंबर, रैंक और रिज़ल्ट में बदल रही है। जरूरत है सख्त रेगुलेशन, बेहतर स्कूल-कॉलेज, मानसिक-स्वास्थ्य सेवाओं और परीक्षा सुधार की। वरना शिक्षा नहीं, स्ट्रेस की फैक्टरी बढ़ती रहेगी।

१. शिक्षा २०२५ का सच
२. कोटा मॉडल अब पूरे देश में कॉपी-पेस्ट
३. बड़े शहरों का कोचिंग प्रेशर
४. कोचिंग इंडस्ट्री की पॉलिश्ड सफलता–छिपे हुए आँकड़े
५. छात्रों की आम स्थिति
६. असली जिम्मेदार कौन?
७. मानसिक-स्वास्थ्य सबसे बड़ा पीड़ित
८. शिक्षा नहीं, स्ट्रेस का उद्योग
९. छात्र–पूरे सिस्टम का सबसे कमजोर पक्ष

कोचिंग मॉडल कैसे बना एक हाई-प्रेशर सिस्टम!

२०२५ का भारत खुद को दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिनाने में गर्व महसूस करता है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कौशल भारत – सरकार हर मंच पर 'युवा-केंद्रित विकास' का दावा करती है। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि आज शिक्षा उम्मीद से ज़्यादा एक बिज़नेस मॉडल बन चुकी है। विशेषकर जिस जगह सबसे ज़्यादा पैसा बह रहा है–कोचिंग इंडस्ट्री–वह अब शिक्षा का 'सपोर्ट सिस्टम' नहीं, बल्कि उसका 'मालिक' बन गई है।

बच्चों के सपनों का बोझ, पैरेंट्स की महत्वाकांक्षाएँ, और सरकारी शिक्षा सिस्टम की कमज़ोर हालत – इन सबका लाभ उठाकर कोचिंग सेंटर एक अलग ही समानांतर व्यवस्था बन चुके हैं। और इस व्यवस्था में छात्रों की भूमिका सीधी हैः वे ग्राहक हैं–जिनके सपनों की कीमत लगाई जाती है। यह रिपोर्ट किसी एक

'विशेष' को पकड़कर खत्म नहीं कर रही। यह पूरी चेन की परतें उधाड़ रही है– क्योंकि दोष सिर्फ कोचिंग का नहीं है, पूरे सिस्टम का भी है। भारत की शिक्षा व्यवस्था २०२५ में एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ छात्रों के भविष्य का नियंत्रण धीरे-धीरे कोचिंग इंडस्ट्री के हाथों में खिसक चुका है। स्कूल-कॉलेजों की गुणवत्ता पर भरोसा टूट चुका है, सरकारी नौकरियों की संख्या सीमित है, और प्रतियोगी परीक्षाओं

१९९०-२००० के दशक में कोचिंग सिर्फ सपोर्ट सिस्टम था। लेकिन २०१० के बाद बोर्ड परीक्षा, JEE–NEET, UPSC, बैंकिंग और SSC जैसी परीक्षाओं में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने एक ऐसा बाजार खड़ा किया जिसे अब कोचिंग इंडस्ट्री कहा जाता है–एक ऐसा उद्योग जिसकी कीमत हजारों करोड़ है, पर विनियमन लगभग शून्य। यह इंडस्ट्री अब सिर्फ पढ़ाती नहीं–फिल्टर करती है, छाँटती है, और छात्रों को नंबरों में बदल देती है।

छात्र बताते हैंः अगर दो टेस्ट खराब गए तो हमें लगता है कि ज़िंदगी खत्म हो गई।' १५-१७ घंटे पढ़ाई की अपेक्षा करना मतलब यह अध्ययन नहीं, बल्कि 'मैराथन स्ट्रेस' है। मनोवैज्ञानिक सपोर्ट लगभग नाममात्र, करोड़ों की इंडस्ट्री में मानसिक-स्वास्थ्य काउंसलिंग पर खर्च शर्मनाक रूप से कम है। कोटा की समस्या यह है कि बाकी देश ने भी इसका कॉपी-पेस्ट शुरू कर दिया है।

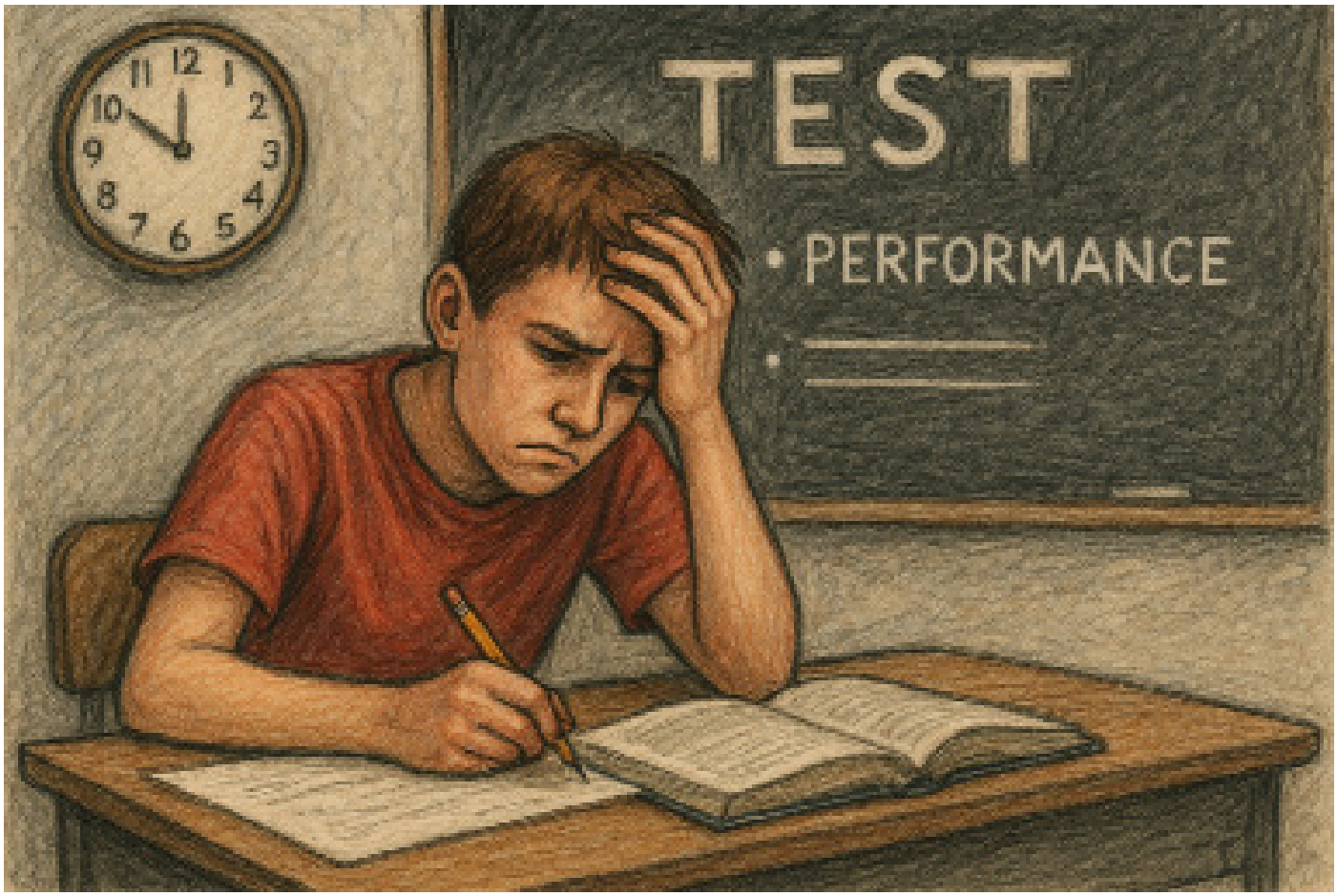

का दबाव पहले से दस गुना बढ़ चुका है। इसी माहौल में देशभर के बड़े शहर–कोटा, दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई–छात्रों के लिए 'तैयारी केंद्र' नहीं, बल्कि एक कठोर सर्वाइवल जोन बन गए हैं। इस रिपोर्ट का उद्देश्य किसी एक शहर या किसी एक कोचिंग संस्था को निशाना बनाना नहीं है। समस्या व्यापक है, फैली हुई है, और सभी जगह लगभग एक ही पैटर्न पर काम कर रही है। इसलिए सभी प्रमुख शहरों का संतुलित विश्लेषण शामिल किया गया है।

कोटाः देश का 'प्रेशर कूकर' मॉडल जहाँ से पूरी कहानी शुरू हुई। १० लाख से ज़्यादा छात्र हर साल कोटा आते हैं। टेस्ट-सीरीज, रैंक, बैच परिवर्तन, और हर महीने की स्क्रीनिंग–यहाँ की सिस्टम ने 'कड़ी मेहनत' और 'क्रूर मेहनत' के बीच की रेखा मिटा दी है।

कोटा मॉडल की गंभीर समस्याएँः

रैंक-आधारित बैच कल्चरः टॉप बैच में आने का दबाव छात्रों की नींद तक खो देता है। लाइन से हट जाना मतलब फेल मान लेनाः कई

दिल्ली–मुखर्जी नगर और करोल बाग की UPSC फैक्टरी

UPSC का आकर्षण और सरकारी नौकरी की प्रतिष्ठा ने दिल्ली को 'UPSC का शहर' बना दिया है। लेकिन यहाँ की स्थिति रोमांटिक नहीं, बल्कि हकीकत यह हैः क्लासें ४००-६०० बच्चों की PG में ३-४ लोग एक छोटे कमरे में, रोज़ १२-१४ घंटे की पढ़ाई, टेस्ट-सीरीज का लगातार दबाव, असफलता की दर लगभग ९७-९८%। यहाँ छात्र सिर्फ 'पढ़' नहीं रहे–वे प्रतिस्पर्धा में घुल रहे हैं। सफलता कुछ को मिलती है, लेकिन तनाव,

अवसाद और अकेलापन लगभग सभी को।

पुणे–FC रोड और कोथरुड का इंजीनियरिंग-MBA सर्किट

पुणे को अक्सर 'स्टूडेंट सिटी' कहा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यहाँ भी कई कोचिंग सेंटर डिग्री से ज्यादा टेस्ट-स्कोर पर जोर देते हैं। भारी फीस, हॉस्टल/PG का बढ़ता किराया, छात्रों को टेस्ट-सीरीज की मशीन बना देना, असफल होने पर छात्रों को 'औसत' या 'अनफिट' करार देना। कई छात्र यहाँ बताते हैं कि उन्हें खुद के लिए एक घंटा भी नहीं मिलता।

बेंगलुरु–Marathahalli/ Koramangala के IT Bootcamps

यहाँ 'स्किल' के नाम पर नए कोर्स हर महीने लॉन्च होते हैं– Data Science, Full Stack, AI, Cybersecurity–कुछ सही, कुछ सिर्फ मार्केटिंग। गंभीर समस्या यह है कि १००% प्लेसमेंट का वादा झूठा/अधूरा होता है, बैचों में २००-३०० छात्र, महंगी फीस, प्लेसमेंट सिर्फ टॉप १०-१५% छात्रों तक सीमित बाकी छात्रों पर आर्थिक और मानसिक बोझ। यह भी एक प्रकार का मॉडर्न कोचिंग ट्रैप है।

हैदराबाद—Ameerpet की टेक और गवर्नमेंट जॉब कोचिंग लैब

अमीरपेट अपनी सस्ती और तेज़ कोर्स प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसका उल्टा पहलू यह है कि क्लासें लाइन-प्रॉडक्शन जैसी गुणवत्ता असमान, छात्र लगातार mock test और assessments से थक जाते हैं।

मुंबई–Dadar, Andheri और Nerul का महंगा लेकिन दबावपूर्ण मॉडल

मुंबई की कोचिंग समस्या थोड़ी अलग है– यहाँ पढ़ाई से ज़्यादा संघर्ष जीवन-यापन का है। PG का किराया आसमान छूता है, रोज़ की ट्रैवल थकाने वाली। बैंकिंग, SSC, रेलवे परीक्षा की भीड़। कोचिंग सस्ते नहीं, लेकिन क्वालिटी हर जगह बराबर नहीं। ऊपर से परिवार से दूर रहने का दबाव और नौकरी की अनिश्चितता। मुंबई में सर्वाइवल का खर्च छात्रों को मानसिक रूप से पहले ही थका देता है। छात्रों की वास्तविक स्थिति (देशभर के हब की कॉमन समस्या) देश के किसी भी बड़े कोचिंग हब में चले जाओ– मानसिक थकान और दबाव की तस्वीर लगभग

एक जैसी है:

- १२-१६ घंटे पढ़ाई
- नींद की कमी
- लगातार टेस्ट
- रिज़ल्ट का डर
- तुलना की संस्कृति
- रिश्तों और परिवार से दूरी
- हाइपर-कंपटीशन
- आर्थिक तनाव
- अपराधबोध (guilt)

anxiety और कई बार depression की ओर बढ़ाव। कई छात्रों के लिए यह 'पढ़ाई' नहीं, बल्कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की लड़ाई बन चुका है।

डेटा जो चुभता है – लेकिन अनदेखा किया जाता है

NEET में कुल छात्रों का २-३% ही टॉप कोचिंग से सफल होता है। JEE में टॉप 5000

रैंक में आने वाले छात्रों की संख्या, कुल कोचिंग आबादी की तुलना में नगण्य है।

ड्रॉपआउट रेशियो ३०-४०% तक। कोचिंग फीस साल-दर-साल १०-२०% बढ़ रही है। मानसिक स्वास्थ्य मामलों में कोचिंग शहरों में तीव्र वृद्धि (साइकोलॉजिस्ट्स इसे 'Performance Anxiety Cluster' कहते हैं)। कोटा में सालाना आत्महत्या मामलों की खबरें लगातार लाइमलाइट में रहती हैं। यह डेटा एक बात स्पष्ट करता है: मांग ज़्यादा है, पर सफलता बहुत सीमित। तो फिर बच्चे क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि सिस्टम उन्हें कहीं और विकल्प देता ही नहीं।

छात्रों की आपबीती

केस १: आदित्य (गाजियाबाद, १७ वर्ष) NEET की तैयारी कर रहा है। पिता प्राइवेट नौकरी में, माँ गृहिणी। कोचिंग, हॉस्टल, रहने-खाने में लगभग २.७ लाख/वर्ष खर्च।

आदित्य की असली समस्या उसकी बुद्धि नहीं बल्कि वह सपना जो उसका नहीं, उसके पिता का है। हर हफ्ते टेस्ट में रैंक गिरने पर कोचिंग की सलाह – 'बैच अपग्रेड लो, रिवीज़न पैक लो।'

मतलब और पैसा।

आदित्य हर रात यही सोचकर सोता है कि 'अगर मैं नहीं बना, तो पापा क्या कहेंगे?'

केस २: शालिनी (छपरा, बिहार; १८ वर्ष) SSC और बैंक की तैयारी करने दिल्ली आई। कमरे में तीन लड़कियाँ रहती हैं, सब पार्ट-टाइम काम करती हैं। क्योंकि कोचिंग फ़ीस २०-३० हज़ार है, और टेस्ट सीरीज़ अलग। उसकी समस्या सिर्फ गरीबी नहीं– उसकी समस्या यह है कि कोचिंग बाज़ार उसे एक कम-कमाने वाली ग्राहक समझता है। उसका विकल्प है, सस्ते यूट्यूब चैनल, टॉपर्स के नोट्स, सेकेंड-हैंड गाइड, और दिन में ५ घंटे की पार्ट-टाइम नौकरी। यह कहानी उस भारत की है जहाँ पैसा ही असली सिलेबस बन चुका है।

केस ३: राहुल (नागपुर, १७ वर्ष) JEE की तैयारी कर रहा है। उसने कोचिंग जॉइन नहीं की–Self Study और Online Resources पर भरोसा करता है। वह स्पष्ट मानता है: 'कोचिंग सिर्फ स्ट्रक्चर देती है, दिमाग नहीं।'

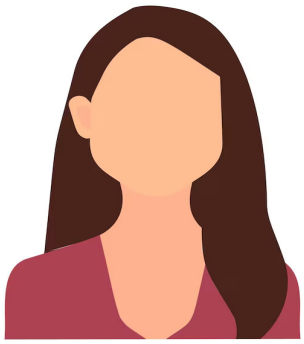

लेकिन उसकी समस्या यह है– समाज उसे 'कम सीरियस' समझता है। दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, सब पूछते हैं: 'कोचिंग नहीं जॉइन की? फेल हो जाएगा!' उसके लिए कोचिंग कल्चर की सबसे बड़ी त्रासदी यही है– आपकी मेहनत को लोग तब तक वैल्यू नहीं देंगे जब तक आपके पास एक 'ब्रांडेड कोचिंग' की रसीद न हो।

मुंबई के छात्रों की असली सच्चाई यह है कि PG का किराया पढ़ाई से बड़ा स्ट्रेस बन चुका है, दादर-परैल-वडाला में एक छोटा कमरा: १८,०००-२५,००० सिर्फ बेड स्पेस, किचन + वॉशरूम शेयर्ड। ३-४ लड़के एक ही कमरे में भरे हुए। कई छात्र सीधा कहते हैं: 'एडमिशन से ज्यादा डर PG खरीदता है।' Mumbra, Kalyan, Vasai, Virar से आने वाले छात्र रोज़ २-३ घंटे सिर्फ खड़े रहकर सफर करते हैं। कई छात्र कहते हैं: 'क्लास पहुँचे-पहुँचे ही आधी ऊर्जा खत्म हो चुकी होती है।'

मुंबई में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है। समस्या यह है कि बैचों में १५०-३०० छात्र Doubt-solving सिर्फ नाम का। Mock tests पर इतना जोर कि छात्र strategy बना ही नहीं पाते।

मुंबई में कई छात्र survival के लिए काम भी करते हैं: Café jobs, Delivery, Retail shifts,Call centers, Night shifts ये बच्चे ८-१० घंटे काम करने के बाद क्लास में पहुँचते हैं तो उनकी हालत क्या होती है? 'नींद पूरी नहीं होती, दिमाग सुन्न रहता है, लेकिन क्लास मिस करने का डर ज्यादा है।'

मुंबई में छोटे घरों में पढ़ने की जगह नहीं होती। इसलिए लाइब्रेरी पर निर्भरता बहुत अधिक है, सुबह ६ बजे से लाइन, ८००-२००० रुपए प्रति महीना। कई लाइब्रेरी पूरी तरह भर

जाती हैं एक छात्र के शब्दों में 'लाइब्रेरी में सीट मिल गई तो दिन सफल, नहीं मिली तो पूरा दिन खराब।'

कई छात्रों के परिवार सोचते हैं कि 'मुंबई

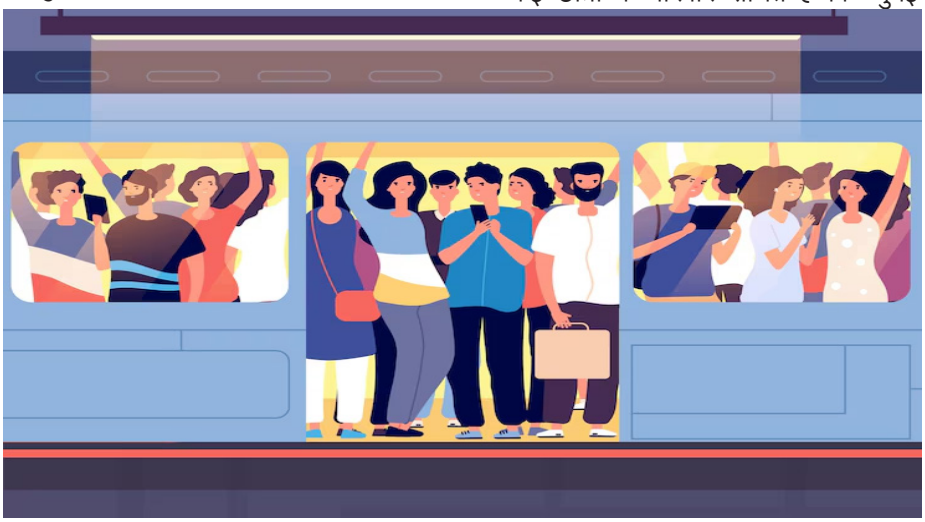

इस हालत का दोषी कौन?

दोष सिर्फ कोचिंग का नहीं है और सिर्फ छात्र या माता-पिता का भी नहीं। समस्या का स्ट्रक्चर गहरा है। पूरी व्यवस्था गलत है क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री वैक्यूम में नहीं बनी–उसे हमने, सिस्टम ने, और समाज ने बनाया है।

१. कोचिंग मालिक – सपनों का व्यवसाय

कोचिंग मालिक बच्चों को इंसान नहीं, इन्वेकोचिंग इंडस्ट्री का ओवर-प्रमोशन

'हमारे यहाँ AIR 1 आया!'

'५०० selections!'

'टॉपर हमारी क्लास से!'

टॉपर को प्रमोट करते हैं, लेकिन ९९% फेल होने वालों का डेटा कभी सामने नहीं आता।स्टमेंट यूनिट की तरह देखते हैं।

टॉपर = विज्ञापन का चेहरा

फेल छात्र = 'उसने मेहनत नहीं की' बयान

बैच अपग्रेड = अतिरिक्त पैसा

टेस्ट सीरीज़ = पैसा

Doubt Sessions = पैसा

Crash Course = पैसा

यह एक बिज़नेस है – और बिज़नेस लाभ देखता है, भावनाएँ नहीं।

२. माता-पिता – अवास्तविक सपनों के निर्माता

बच्चा ६०% लाया हो या ९५% – लक्ष्य हर किसी के लिए डॉक्टर और इंजीनियर।

विज्ञान चुनो

इंजीनियर/डॉक्टर बनो

सरकारी नौकरी लो

प्राइवेट नौकरी को अस्थिर मानना

पड़ोसी/रिश्तेदार से तुलना

यह मानसिक दबाव बच्चों को शुरुआत से ही एक ट्रैक पर धकेल देता है–जैसे विकल्प हैं ही नहीं। 'हमारा बेटा कुछ बड़ा करेगा' का दबाव, कोचिंग की मार्केटिंग देखकर दिमाग फिर जाना, कई पैरेंट्स खुद को आधुनिक समझते हैं, पर बच्चों पर दबाव डालने में उनसे बड़ा कोई 'दोषी' नहीं।

३. सरकार – निरीक्षण और रेगुलेशन में पूरी तरह फेल

सरकार ने स्कूलों को इतना कमजोर छोड़ दिया कि छात्र को मजबूरी में कोचिंग पर निर्भर

होना पड़ता है। न कोचिंग की फीस-सीमा, न लाइसेंसिंग सिस्टम, न टीचर्स की क्वालिटी चेक और तो और न छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा!

सरकार का रवैया स्पष्ट है:

'कोचिंग चल रही है, तो चलने दो।'

४. स्कूल – नाम के लिए शिक्षा, काम के लिए नहीं

स्कूल अब बस दो काम करते हैं: फीस लेना और बच्चों का attendance लेना

CBSE और राज्य बोर्ड दोनों में

स्कूल की गुणवत्ता गिर चुकी है।

क्लासरूम सीखना इतना कमजोर है कि

किसी बच्चे को लगे कि 'मैं स्कूल से JEE/NEET पास कर सकता हूँ'– यह बात अब मजाक लगती है। यानी कोचिंग इंडस्ट्री का असली बूस्टर स्कूलों की नाकामी है।

सोशल मीडिया और Fear of Missing Out (FOMO)

हर कोई दिखा रहा है कि वह 'कुछ बड़ा' कर रहा है। छात्रों को लगता है–'मेरे साथ ही कुछ गलत है।'

कोचिंग सेंटर का मनोवैज्ञानिक खेल – दिमाग से पहले आत्मविश्वास तोड़ते हैं

कोचिंग की मार्केटिंग रणनीति सीधी है: पहले तुम्हें डराओ 'NEET बहुत कठिन है, बिना कोचिंग पास ही नहीं होगा।' फिर तुम्हें हीनभावना दो 'ब्रांडेड कोचिंग में ही असली गाइडेंस है।' फिर तुम्हें पैसों के हिसाब से बैच में बाँट दो

Super Batch, Premium Batch, Average Batch, Low Batch

जो बच्चा 'Low Batch' में जाता है, उसका आत्मविश्वास आधा वहीं टूट जाता है। कोचिंग का इरादा साफ है– तुम्हें निर्भर बनाना, मजबूत नहीं।

क्या समाधान है?

यह सिस्टम बनाम छात्र की लड़ाई है–जहाँ छात्र सबसे कमजोर पक्ष है। कोटा, दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई–सभी जगह समस्याएँ अलग-अलग दिखती हैं, लेकिन जड़ एक ही है: अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, अव्यवस्थित कोचिंग इंडस्ट्री, सामाजिक दबाव और शिक्षण संस्थानों की कमजोरी। अगर हम अभी नहीं जागे, तो आने वाले सालों में शिक्षा नहीं, बल्कि स्ट्रेस का उद्योग बढ़ेगा–और उसके नीचे छात्रों का भविष्य दबता जाएगा। सिस्टम टूटा है, इसे फिर से बनाना होगा। और यह काम सिर्फ सरकार का नहीं–समाज का भी है।

१. कोचिंग के लिए राष्ट्रीय लाइसेंसिंग सिस्टम, जो डॉक्टर, इंजीनियर लाइसेंस से चलते हैं, वैसे ही कोचिंग भी लाइसेंस से चले।

२. फीस कैप – हर राज्य में तय रेंज

२-३ लाख फीस किसी भी स्तर पर वाजिब नहीं।

३. मानसिक स्वास्थ्य काउंसलर अनिवार्य

हर बड़े कोचिंग कैंपस में full-time psychologist हो।

४. मार्केटिंग कंट्रोल – टॉपर का चेहरा ना बनाओ, टॉपर ब्रांडिंग पर पाबंदी लगे। सिर्फ सीखने का मॉडल दिखाओ, व्यक्ति नहीं।

५. स्कूल सिस्टम की मरम्मत

क्लासरूम टीचिंग को मजबूत किए बिना कोचिंग कल्चर खत्म होना नामुमकिन है।

६. Alternative Career Awareness को राष्ट्रीय अभियान बनाओ। बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि डॉक्टर-इंजीनियर बनने के अलावा भी दुनिया है।

Wholesale Furniture Market
Ulhasnagar,Mumbai

सस्ते फर्नीचर के 5 थोक बाजार
फर्नीचर खरीदिए आधे दामों पर
एक से बढ़कर एक एंटीक आइटम

भारत की कोचिंग इंडस्ट्रीः उतार-चढ़ाव, दबाव, और टूटता हुआ मॉडल

भारत की कोचिंग इंडस्ट्री पिछले तीन साल में जितनी तेज़ी से बदली है, उतनी तेजी किसी भी शिक्षा-संबंधी सेक्टर में शायद ही कभी देखी गई हो। Kota, जो कभी IIT-JEE और NEET तैयारी का 'मेगासिटी' माना जाता था, आज पहली बार गहरे झटके झेल रहा है। वहीं Delhi, Pune, Hyderabad और Bengaluru जैसे शहरों का कोचिंग बाजार बढ़ भी रहा है और टूट भी है। यह बदलाव डिमांड में गिरावट नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की संरचना बदलने का संकेत है।

तीन साल पहले, कोटा की अर्थव्यवस्था अपने शिखर पर थीः 2022 में अनुमानित coaching economy: ₹10,000–11,000 करोड़, 2023 में यह बढ़कर ₹11,000–12,000 करोड़, लेकिन 2024–25 में सीधा गिरकर ₹8,000–8,500 करोड़।

Student enrolment तीन साल में पहली बार इतना नीचे आयाः १.७५ लाख → १.२० लाख

यानी ५०,०००+ छात्रों का पलायन।

होस्टल और PG occupancy भी 30%–40% तक नीचे, और stationery–से-transport जैसे Kota-dependent व्यवसायों में 20–35% की गिरावट।

सफलता की कहानी कम, संघर्ष की कहानी ज़्यादा है। बहुत से छात्र १-२ साल पढ़ते हैं, फिर भी ट्रेनिंग ले लेते हैं, नौकरी पकड़ लेते हैं, घर लौट जाते हैं , Preparation छोड़ देते हैं, या किसी और कैरियर में मुड़ जाते हैं और यह गलत नहीं – ये practical होता है। मुंबई आपको बहुत जल्दी 'ground reality' समझा देती है। मुंबई में पढ़ाई का असली मुकाबला किताबों से नहीं – किराए, ट्रेनों, भीड़, खर्चों, और मानसिक दबाव से है।

Allen—Kota की रीढ़-का profit FY23 के ₹429 करोड़ से FY25 में ₹41 करोड़ पर पहुंच गया।

Kota का पूरा model ही दबाव, आत्महत्या के मामलों, online competition और multi-city expansion की वजह से कमजोर पड़ चुका है।

Delhi: Mukherjee Nagar और Karol Bagh की स्थिर लेकिन दबावभरी दुनिया

UPSC और SSC की तैयारी ने Delhi का coaching hub अब भी मजबूत रखा हैः

2022: ₹2,000–2,200 करोड़

2023: ₹2,500–2,700 करोड़

2024–25: ₹2,800–3,000 करोड़

Growth है, लेकिन दिल्ली तीन बड़े दबाव झेल रही हैः

Edtech और YouTube lectures की मुफ्त उपलब्धता

PG कीमतों की ऊँचाई

Repeated attempts करने वाले छात्रों की संख्या में कमी

Mukherjee Nagar अब भी देश का सबसे बड़ा UPSC cluster है, लेकिन 'offline ही सब कुछ है' वाली कहानी अब टूट चुकी है।

Pune का coaching market शांत भी है और स्थिर भीः

2022: ₹600–700 करोड़

2023: ₹700–850 करोड़

2024–25: ₹800–900 करोड़

यहाँ Kota जैसा pressure-culture नहीं है, इसलिए growth organic है–लेकिन scale Kota के स्तर तक कभी नहीं पहुंचेगा।

Hyderabad: नया उभरता Coaching Powerhouse

A-Circuit से लेकर ACJU Tech तक, Hyderabad ने engineering + government exams में अपना बड़ा footprint बना लिया हैः

2022: ₹900–1,000 करोड़

2023: ₹1,050–1,200 करोड़

2024–25: ₹1,200–1,300 करोड़

Kota की गिरावट का फायदा मिला है।

Hyderabad को Kota-style pressure hub बनने से रोकने वाली चीज इसकी diverse student mix है–tech, software, GATE, और jobs का संतुलित ecosystem~

Bengaluru: Fragmented लेकिन growth-ready बाजार

Bengaluru में कोई Kota जैसा cluster नहीं है, लेकिन coaching market फैल रहा हैः

2022: ₹500–60० करोड़

2023: ₹600–700 करोड़

2024–25: ₹700–800 करोड़

यहाँ demand stable है लेकिन institutes बहुत बिखरे हुए हैं–SHDT, KDDUA जैसे hubs अभी शुरुआती stage में हैं।

Industry-Level Picture: India Coaching Market (२०२२-२०२५)

वर्ष	इंडस्ट्री साइज (अंदाजन)
२०२२	₹५८,०००-६०,००० करोड़
२०२३	₹६२,०००-६५,००० करोड़
२०२४-२५	₹६०,०००-६३,००० करोड़

Growth रुकी नहीं है, लेकिन profitability नीचे है–almost हर बड़े brand में यही trend है।

The Real Shift: Coaching सिर्फ़ बिज़नेस नहीं, अब एक संघर्ष का मॉडल। पिछले तीन साल में तीन चीज़ें crystal clear हो गई हैंः

१. Offline monopoly टूट चुकी है

YouTube और hybrid learning ने coaching को affordable बना दिया है–और यह coaching institutes की pricing power खत्म कर रहा है।

२. Parents अब पहले जैसे खर्चा नहीं कर पा रहे

₹१.५-२ लाख per year की fees middle-class family की limit को तोड़ रही है।

3. Students numbers down → profit down → expansion up → pressure up। यानी institutes जितना expand कर रहे हैं, उतना ही financially fragile भी हो रहे हैं। ■